



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 1992/फाल्गुन 23, 1913
No. 45] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 1992/PHALGUNA 23, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रचा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना सं० 281-आईटीसी (पीएन)/90-93

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1992

विषय: 1991-92 के लिए 719 मिलियन येन की जापानी अनुदान
सहायता के अंतर्गत-गवर्नमेंट कालिज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे में
उपस्कर के आयात से संबंधित लाइसेंसिंग शर्तें।

काइल सं. आई पी सी/23(89)/90-93.--1991-92 के लिए
719 मिलियन येन (719,000,000 येन) की जापानी अनुदान सहायता
के अंतर्गत गवर्नमेंट कालिज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में उपस्करों के आयात
और जापान से भारत के पत्तनों को उपस्कर के परिवहन के लिए अपेक्षित
सेवाओं संबंधी शर्तें जो इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं,
एतद्वारा सूचना के लिए अधिसूचित की जाती हैं।

डी. आर. मेहता, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं. 281-आईटीसी
(पीएन)/90-93 दिनांक 13-3-92 का परिशिष्ट।

वर्ष 1991-92 के लिए 719 मिलियन येन (येन 719,000,000)
की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत गवर्नमेंट कालिज ऑफ इंजी.
नियरिंग, पुणे के लिये उपस्कर का आयात और उपस्कर का भारतीय
पत्तनों पर परिवहन के लिये आवश्यक सेवाओं हेतु लाइसेंसिंग
शर्तें —

(खंड 1) सामान्य शर्तें

1(1). वर्ष 1991-92 के लिए 719 मिलियन येन की जापानी अनुदान
सहायता उपस्कर के आयात के लिए और उनके भारतीय पत्तनों
पर परिवहन के लिए सेवाओं के लिए संभारकों को दी जाने
वाली सहायता के वित्त पोषण के लिए है।

1(2). आयातक के नाम में आयात लाइसेंस कुल मिलाकर 790 मिलियन
येन (आयात बीमा भाड़ा) मूल्य से अधिक के लिए जारी नहीं किए जाने
चाहिए और उन पर एक शीर्षक 1991-92 के लिए 719 मिलियन येन की
जापानी अनुदान सहायता होना चाहिए। प्रथम और द्वितीय प्रत्यय के लिए

लाइसेंस कोड "एस/जे एल" होगा। परंतु सामान्य खुले लाइसेंस के अंतर्गत जाने वाली मर्चों के लिए कोई आयात लाइसेंस अपेक्षित नहीं है।

1(3). विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति आयात लाइसेंस के लिये नहीं दी जाएगी। भारतीय अधिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी भुगतान भारतीय अधिकर्ता को भारतीय रुपये में किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और लाइसेंस पर ही प्रभावित किए जाएंगे।

1(4). उपरकर की प्राप्ति इस अनुदान के अंतर्गत जापान से ही की जाए।

1(5). आयात लाइसेंस लागत बीमा भाड़ा आधार पर जारी किया जाएगा जो कि 8-12-92 तक वैध रहेगा।

1(6). संविदा में नकब आधार पर अर्थात् बैंक आफ इंडिया, टोकियो को जापानी संभरकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। उसमें सुपुर्दगी की अवधि के लिए भी इस प्रकार व्यवस्था होनी चाहिए:—

"सुपुर्दगी 8-12-92 तक पूर्ण की जानी है"।

1(7). संविदा का मूल्य लागत और भाड़ा या जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य आधार पर येन में दर्शाया जाना चाहिए (येन को भिन्न को हटा दिया जाना चाहिए) और भारतीय अधिकर्ता का कमीशन यदि कोई हो तो शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अन्य किसी मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परिस्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए। जहाज पर्यन्त निःशुल्क लागत और भाड़ा धनराशि भ्रमण-भ्रमण प्रदर्शित की जानी चाहिए, परंतु ठेके में यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाड़ा का खर्च वास्तविक आधार पर देय होना या ठेके में निर्दिष्ट किए गए भाड़े का खर्च वास्तविक खर्चों के अतिरिक्त देय धनराशि होगी।

1(8). नव संविदा जापानी येन में केवल जापानी राष्ट्रियों या जापानी राष्ट्रों द्वारा नियंत्रित जापानी बैंक व्यक्तियों के साथ की जानी चाहिए। एक प्रमाण पत्र (दो प्रतियों में) जिसमें संभरक की पात्रता दर्शायी गई हो प्रत्येक संविदा के साथ जोड़ी जानी चाहिए।

खंड 2—संभरक ठेका में निम्नलिखित शर्तें विंश रूप से समाविष्ट होनी चाहिए:—

2(1). 1991-92 का लिए 719 मिलियन येन की अनुदान सहायता के संबंध इस संविदा की व्यवस्था 9 दिसंबर, 1991 को भारत और जापान का सरकार के बीच हुए समझौते के अनुसार की गई है और वह दोनों सरकारों के अनुमोदन के अधीन होगी।

2(2). विदेशी संभरकों को भुगतान उस भुगतान के लिए "प्राधिकार पत्र (ए/पी) के माध्यम से किया जाएगा जो 1991-92 के लिए जापानी अनुदान सहायता के अधीन बैंक आफ इंडिया, टोकियो के दाम में सहायता एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, इंडियन आयल भवन, 5वां तल (बी. विंग) जसपथ नई दिल्ली-110001 द्वारा जारी किया जाएगा।

2(3). जापानी संभरक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए सहमत है जो एक ओर भारत सरकार द्वारा और दूसरी ओर जापान सरकार द्वारा अपेक्षित है।

2(4). जापानी संभरक भारतीय दूतावास टोकियो के साथ विचार विमर्श करके पोतलदान की व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गया हो और उस उद्देश्य से वह शामिल माल की डिलीवरी के कार्यक्रम के बारे में भारतीय दूतावास, टोकियो को सूचित करता रहेगा और कम से कम छः हफ्ते पहले अपेक्षित पोतलदान की अधिसूचना भारतीय दूतावास को देगा ताकि समुचित व्यवस्था की जा सके। अपवाद स्वरूप अगर आयातकर्ता यह सो नोटिस की इस अवधि को कम किया जा सकता है। जापानी संभरक प्रत्येक पोतलदान के बाद आयातकर्ता को केवल द्वारा आवश्यक और की सूचना देने के लिए भी सहमत होगा तथा उसकी एक प्रति भारतीय दूतावास, टोकियो को भेजी जाएगी।

खंड 3—भारत सरकार और जापान द्वारा ठेके का अनुमोदन

3(1). जैसे ही शर्तों का अंतिम रूप दे दिए जाने ह, लाइसेंसधारी को दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित ठेके की पांच प्रतियां या जापानी संभरकों को भारतीय आयातक द्वारा दिए गए नव आदेश के साथ जापानी संभरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश की चार प्रतियों सहित सभी प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों के साथ अनुबंध-1 के प्रपत्र में "ए/पी" जारी करने के आवेदन की दो प्रतियों सहित भवर सचिव (आयन आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को भेजनी चाहिए। उपर्युक्त प्रक्रिया संविदा की विषय दस्तु या उसकी कीमत के आवश्यक आणवधनों से उत्पन्न सभी संविदा संशोधनों के लिए भी लागू होगी।

3(2). वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), जापान अनुभाग, 1991-92 के लिए 719 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अधीन वित्तदान देने के लिए संविदा की दो प्रतियां जापान सरकार को अनुमोदन के लिए भेजेगा और इसी के साथ-साथ उपर्युक्त (1) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक-एक सेट लेखा व लेखा परीक्षा निबंधक और भारत के दूतावास, टोकियो को भी भेजा जाएगा।

3(3). जापान सरकार से ठेका अनुमोदन प्राप्त करने के बाद वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लॉक जापान अनुभाग उसका सूचना सहायता लेखा व लेखा परीक्षा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, इंडियन आयल भवन 5वां तल बी विंग जसपथ, नई दिल्ली-110001 को देगा जो कि जापानी संभरक को भुगतान प्राधिकार पत्र (ए/पी) जारी करेगा। प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्रतियां भारत सरकार का दूतावास टोकियो, आयातक भारत में आयातक के बैंक और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के जापान अनुभाग को भेजी जाएगी।

3(4). भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की प्राप्ति के बाद बैंक आफ इंडिया टोकियो जापान सरकार, भारत का राजदूतावास, टोकियो, भारत में आयातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक को सूचना देने हुए इस प्राप्ति की सूचना में संभरक को अवगत कराया।

3(5). पोतलदान करने के बाद जापानी संभरक अपने बैंकों के माध्यम से ए/पी में उल्लिखित दस्तावेज बैंक आफ इंडिया, टोकियो को प्रस्तुत करेगा यदि दस्तावेज सही पाए गए तो बैंक आफ इंडिया, टोकियो दस्तावेजों में उल्लिखित धनराशि जापानी संभरक को अपने बैंकों के माध्यम से रिहा करेगा।

3(6). जापानी संभरक को भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए बैंक आफ इंडिया, टोकियो को देय बैंकिंग प्रमार्श का भुगतान भारत में आयातकर्ता के संबंधित बैंक द्वारा भारत सरकार के लेखों को प्रभावित किए बिना सामान्य बैंक सूचों के माध्यम से बैंक आफ इंडिया, टोकियो को धन परेषण द्वारा तय किया जाएगा।

खंड 4—रूपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व

4(1). मूल पराक्रम्य पोत परिवहन दस्तावेज बैंक आफ इंडिया टोकियो द्वारा भारत में आयातक के संबंधित बैंक को भेजे जाएंगे जो कि भारतीय स्टेट बैंक या अनुबंध-1 में (ण) पर यथा-उल्लिखित किसी राष्ट्रीय बैंक की एक शाखा होगी जो संबंधित आयातक को पराक्रम्य जहाजरानी दस्तावेज रिहा करने से पूर्व इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जापानी संभरक को चुकाई गई येन भुगतान को समुचित रूप से धनराशि के बराबर रूप में उन मामलों में जहां देने योग्य है, धातु के प्रमार्श सहित मुख्य धरायगी की राशि सहित संभरक को भुगतान कर दिया है और उन धनराशि पर जापानी संभरक को बैंक आफ इंडिया, टोकियो द्वारा भुगतान की तिथि में से वास्तविक रूप से जमा करने की तिथि तक की अवधि पर पहले 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और शेष अवधि के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हिसाब सफाकर धातु सार्वजनिक

सूचना सं. 31-आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 20-8-83 और 35-
"आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 26-8-83 की शर्तों के अनुसार सरकारी
लेखे में जमा कर दिया गया है। व्याज दोनों वित्तों अर्थात् जिस
दिन विदेशी संभरक को भुगतान किया जाता है और जिस दिन
सरकारी लेखे में रकमा किया जाता है, देय है, देखिए
सार्वजनिक सूचना सं. 103-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-76
और सार्वजनिक सूचना सं. 230-आईटीसी (पीएन)/85-88, दिनांक
20-7-87 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं. 74-आईटीसी (पीएन)/
74, दिनांक 31-5-74 आयातक द्वारा किए जाने वाले रुपये निर्यातक
निकटम रुपये में गिना जाएगा। विदेशी संभरक को किए गए येन भुगतान
के समतुल्य रुपये की गणना करने के लिए अग्रतयाजी जाने वाली विनियम की
दर भुगतान की तारीख को लागू विनियम की यह मुश्किल बरहती है।
सार्वजनिक सूचना सं. 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76
तथा सार्वजनिक सूचना सं. 113-आईटीसी (पीएन)/88-91, दिनांक
6-4-89 में निर्धारित तरीके के अनुसार निम्नलिखित की गई हो जो मुख्य
नियंत्रक, आयात-निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय
रिजर्व बैंक के द्वारा विनियम नियंत्रण परिषद के माध्यम से सरकार द्वारा
समय-समय पर घोषित की गई हो। इस संबंध में और व्याज की दर के
संबंध भी जब भी कोई परिवर्तन आवश्यक होगा अधिसूचित कर दिया
जाएगा। यह मुनिश्चित करने के लिए भारतीय बैंक की जिम्मेदारी होगी
कि देय धनराशि आयातकों को आयात दस्तावेज सौंपने से पहले सरकारी
खाते में ठीक प्रकार से जमा कर दी गई है। आयातक को भी यह
मुनिश्चित कर लेना चाहिए कि देय धनराशि अपने ऋणदाताओं से
दस्तावेजों की सुपुर्दगी लेने से पहले सरकारी खाते में ठीक प्रकार से जमा
कर दी गई है। यह मुनिश्चित करने के लिए आयातक को जिम्मेदारी
होगी कि देय धनराशि सरकारी खाते में ठीक प्रकार से सुरक्षित जमा कर
दी गई है अन्य हो अन्य के विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधि-
कारियों से साल की सुपुर्दगी प्राप्त करने है। यदि आयातक सरकार को
देय धनराशि को साल की सुपुर्दगी लेने से पहले जमा नहीं कर पाता तो
आगे के लिए उसे प्राधिकार पत्र देना बन्द कर दिया जाए। जिन लेखा
शीटों में उपर्युक्त रूपया निक्षेप किया जाएगा वह "के डिपॉजिटन एण्ड
एक्वालिज 8443 सिविल डिपॉजिटन-डिपॉजिटन फार परचेजिंग एंटस्ट्रु
एण्ड थ्रुआउट ग्रांट एंड फ्रॉम दि गवर्नमेंट थ्राफ जापान फार 1991-92
ग्रांट, फार दि परचेज, थ्राफ एक्विपमेंट/सिविल थ्राफ गवर्नमेंट कालिज
थ्राफ इजियरिंग पुणे, होगा।

4(2) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमाने के ऊपरी दाहिनी ओर कोने में कोड में 5160000009 का संकेत देते हुए या ऐसा संभव न हो तो पैसा भारतीय स्टेट बैंक या उसकी किसी धनुषी शाखा या किसी राष्ट्रीकृत बैंक (इंजीनियरिंग बैंक) से डिमाण्ड ड्राफ्ट लेकर उसे भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी दिल्ली-6 (इंजीनियरिंग बैंक) को भेजा गया जाए लिखकर सरकार की साख में मासिक संचयन सं. 103-आईटीसी(पीएन)/76, दिनांक 12-10-76 में यथा निर्धारित रूप में जमा होना चाहिए।

4(3) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसा किया जाने के बावजूद विनों के भीतर भारत में संवर्द्ध बैंक भी ऊपर निर्धारित तरीके से यह आतिरिक्त धनगमि सेवा खर्चों के निमित्त भेजेगा जो वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा मांगी जाए। जालान के विभिन्न कालमों को भरते समय आयातकों/उनके बैंकरो को हमें बात को सुविधित कर लेता चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं. 103-1976/टीओ/ (पीएन)/76, दिनांक 12-10-1976 के पैरा 2 में निर्धारित सूचना जालान के कालम "धन परेपण" और प्राधिकारी (यदि कोई हो) के पूर्ण ऊपरे में निरपवाद रूप से निविष्ट किए गए हैं। खजाना जालान में निम्नलिखित ऊपरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए:—

(फ) विस्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक।

(ख) येन मुद्रा को वह धाराशि जिसके संबंध में अपनई गई परिवर्तन की दर के साथ निरोप किए जाते हैं।

(ग) विदशी संभरक को भुगतान करने की तिथि ।

(घ) अक्ष किए गए न्याज की राशि और अजक्षि जितके लिए गिन।
गया है।

(५) कुल जमा राशि ।

(रुवाज की गणना जापानी संभरक को अशायगी की तारीख से और उस तारीख तक जिस तारीख को समकक्ष रूप से सरकारी खाते में जमा कराया है, की जायेगी।

उसके पश्चात् सी. ए. ए. एण्ड ए. द्वारा जारी किए गए प्राधिकार का संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत-परिवर्तन दस्तावेजों की संलग्न करने हुए खजाना खाता खोला जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत शक द्वारा सी. ए. ए. एण्ड ए. को भेजा जाता है।

टिप्पणी.—भारत में आयातक के बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रुपये का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियो" की आयाती की सूचना और अपरिवर्तनीय पोतलदान दस्तावेज की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर निर्यात रूप में किया जाता चाहिए और यह कि उसके तत्काल ब्रब सी. ए. ए. एण्ड ए. वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) नई दिल्ली को सूचित कर दिया जाएगा।

4(4) भारत में संसद भारतीय बैंक को लाइसेंस की मुद्रा विनियम निबंधन प्रति पर रखा निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठान्त करना चाहिए और अपेक्षित "एच" प्रत्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक, ब नई की भोजना चाहिए।

ॐ पु३--५ विधि व्यवस्थापं

5(1) अनुदान सहायता के उपयोग करने की रिपोर्टें ।

संभरक को को जाने वाली अदायगियों को राशि और तारीख को सुनिश्चित करने के लिए आयातक को अलग से व्यवस्था करती होगी, आयातक के बैंक द्वारा या त्रिलम्ब से प्राप्त पोत परिवहन इत्यादि । प्र नेवों की प्राप्ति को रूपरा निलेन राशि पर देय व्याज राशि को आगिक या पूर्ण रूप में भुक्त करने का कारण नहीं माना जाएगा ।

आयातक का पोतनदान और उसके प्रयोग किए गए भुगतान और शेष धनराशि के बारे में साब पत्र खोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा निबंधक, आर्थिक कार्य विभाग, विश्व मंत्रालय इंडियन आयल भवन, 5वां तल (बी विंग) जनपथ, नई दिल्ली-110001 को भेजनी चाहिए।

5(2) प्रायातक को उन किसी विशेष उद्योगों से संभरक को अवगत करा देता चाहिए जो इस अनुदान सहायता के अर्थात् माल के लाने में संभरक पर प्रभाव डालते हैं ।

5(3) विवाद :- यह सत्य लेना चाहिए कि लासेंसधारी और संभरकों के बीच कोई विवाद उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगी। भारतीय स्टेट बैंक टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें अनुसूच्य-1 में "भुतनाम की शर्तों" के अन्तर्गत प्रच्छी तरह से स्पष्ट कर लेनी चाहिए। संविदा की शर्तों में विवाद के निपटान से संबंध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए।

5(4) भावी अनुदेश :- जापान से 1991-92 के लिए अनुदान सहायता के अंतर्गत आयात लाइसेंस या उनके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले या सभी मामलों से संबंधित या जापान से इस अनुदान सहायता के अंतर्गत सभी आयातों का पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए निदेशों या आदेशों का लाइसेंसधारियों को सख्त पालन करना होगा ।

5(5) शक्तिमण या उल्लंघन :- उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित की गई शर्तों के शक्तिमण या उल्लंघन करते पर प्राप्ता-विषय 1 (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की जायेगी।

5(6) अनुबन्धों की सूची

अनुबन्ध 1—प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध

अनुबन्ध 2—प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

अनुबन्ध 1

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र सेवा में

सहायक लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग,
“बी” विंग 5 वां तल, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली।

विषय :— गवर्नमेंट कालिज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे के लिए 719 मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान से भारत के पत्तनों पर उपस्करों के परिवहन के लिए अपेक्षित उपस्कर और सेवाओं का आयात।

महोदय,

ऊपर उल्लिखित अनुदान सहायता के अधीन जापान से उपकरणों और उनके परिवहन के लिए आवश्यक सेवाओं के संबंध में हम संबंधित जापानी संभरक के पक्ष में बैंक आफ इंडिया, टोकियो को भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र भेज रहे हैं :-

- (क) भारतीय आयातक का नाम और पता।
- (ख) आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य और जब तक यह वैध है।
- (ग) अधिप्राप्ति के तरीके क्या यह प्रत्यक्ष खरीद पर आधारित है या सीमित खुली निविदा पर आधारित है। इस मामले में कारणों सहित यह निर्दिष्ट करना है कि क्या संविदा का निर्णय उपर्युक्त तकनीकी प्रस्ताव के आधार पर किया गया है।
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण।
- (ङ) माल का उद्गम देश।
- (च) संविदा का कुल लागत और भाड़ा मूल्य (येन में)।
- (छ) यदि कोई हो तो भारतीय रुपये में भारतीय एजेंट के कमोशन की धनराशि (येन में)।
- (ज) वह कुल लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में) जिसके लिए भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता है।
- (झ) जापानी संभरकों के साथ की गई संविदा की संख्या और दिनांक जापानी संभरक का नाम और पता।
- (ञ) वे भुगतान और संभारित तिथि जिनको संविदाओं के अंतर्गत देय होंगे।
- (ट) माल की सुदुर्गता पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि।
- (ठ) बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो को भुगतान करने समय प्रस्तुत किए जाने वाले वस्तावेज (प्रत्येक सेट की संख्या और उनका निपटान वसति हुए)।
- (ड) पोतलवान अनुदेश (अनुमेय या गैर अनुमेय वाहनारक्षण/आंशिक पोतलवान निर्दिष्ट कीजिए)।
- (ढ) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता।
- (ण) बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो के प्रभार आयातक अथवा स्प्लार्ड-कर्ता कौन बहन करेगा, रूपया निर्दिष्ट करें।

(त) आयातक द्वारा वचनबद्धता:—“हम एश्वर्य द्वारा वचन देते हैं कि हम विदेशी संभरक को वेध धनराशि के समतुल्य रुपये की पूर्ण धनराशि को सरकार द्वारा निर्धारित क्रियाविधि से और प्रचलित ढर पर सही रूप से जमा करवा देंगे। माल (आयातित सामग्री) के प्रत्येक परेषण की सुदुर्गता से प्राप्त करने से पूर्ण राशि शीघ्र ही जमा करवा दी जाएगी। विदेशी राष्ट्रों की सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में, जैसे ही हमारे द्वारा विदेशी संभरक के संगत बीजक अनुमोदित किए जाते हैं और संभरक को भुगतान किया जाता है वैसे ही राशि जमा करवा दी जाएगी।

अनुबन्ध 2

भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र सं.-----
संख्या एक
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
नई दिल्ली, दिनांक:

सेवा में

बैंक आफ इंडिया
टोकियो शाखा,
टोकियो (जापान)

विषय:—गवर्नमेंट कालिज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे के लिए मिलियन येन की जापानी अनुदान सहायता के अंतर्गत जापान से भारत के पत्तनों पर उपस्करों के परिवहन के लिए अपेक्षित उपस्कर और सेवाओं का आयात भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र जारी करना।

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के साथ 9 दिसम्बर, 1991 में किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार आपको एतद्भाग परिशिष्ट में दिए गए यथासंलग्न ब्योरे के अनुसार सर्वे श्री-----को-----येन धनराशि के भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

2. रूपया भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र (ए/पी) की पावती के बारे में संभरकों की सूचना दे और इसकी प्रत्येक सूचना पत्र की एक प्रति जापान सरकार आयातक बैंक भारत के राजदूतावास, टोकियो और इस मंत्रालय को पृष्ठांकित की जाए।

3. भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान परिशिष्ट में यथा सांकेतिक लवान वस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

4. विदेशी संभरक को भुगतान करने समय (आयातक के बैंक का नाम और पता-----मूल पोत परिवहन वस्तावेज जिसके साथ अतिरिक्त वस्तावेजों का पूरा सेट और संभरक को आयातनी के लिए नामे बीजक की प्रति जिसमें आयातनी यदि कोई हो भेजी जानी चाहिए।

5. आयातक द्वारा आपको वस्तावेज संभरकों एवं बैंकों के प्रभार को भेजने आदि के लिए भाड़े सहित भरा किए जाने वाले बैंकिंग भाड़े आयातक के बैंक के द्वारा सीधे ही निर्धारित किए जाएंगे।

6. जैसे ही जापानी संभरक द्वारा प्रस्तुत किए गए लवान वस्तावेजों आदि के आधार पर आपको द्वारा कोई भी भुगतान किया जाता है तो इसकी सूचना निर्धारित प्रपत्र में इस मंत्रालय को और आयातक बैंक को भेजी जाने चाहिए।

7. इस मंत्रालय को विशेष अनुमति के बिना भुगतान के लिए प्राधिकार पत्र के लिए कोई भी सूचना संगोपन जारी नहीं किया जा सकता है।

8. यह भुगतान प्राधिकार पत्र-----तक वैध रहेगा।

9. इस अधिकार पत्र के शर्तों पर दिया जाता है दस्तावेजों से संबंधित सारे प्रवाचार में और बीजक में अवाधगी दर्शाते हुए भी इसे लिया जाए।

भवदीय,

(लेखा अधिकारी)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:

1. आयातक-----को उसके पत्र सं-----
दिनांक के-----के संदर्भ में।

उत्तरे अनुरोध है कि वे बैंकों से विनिमय दस्तावेजों की डिलीवरी लेने से पूर्व निर्धारित दर पर और तरीके से अपने बैंकों के माध्यम से रुपया, निक्षेप प्राप्त करना का प्रबंध करें। यदि विशेष परिस्थितियों के कारण माल की डिलीवरी सीधे ही सीमाशुल्क और पतन प्राधिकारियों से मूल पोत लदान दस्तावेज भेजे बिना ही प्राप्त कर ली गई हो तो डिलीवरी लेने से पूर्व ही निक्षेप किए जाने चाहिए। विदेशी राष्ट्रों द्वारा दी गई सेवाओं के लिए भुगतान के मामले में ही सम्बन्ध बीजक भुगतान के लिए अनुमोदित हो जाएं, निक्षेप कर दिए जाएं। निक्षेप जल्दी ही और ठीक से न करने पर लाइसेंस की शर्तों में यथा उल्लिखित आवश्यक कार्य-वाही की जा सकती है।

2. आयातक के बैंक-----

(1) यह प्राधिकार पत्र येन क्रेडिट के अंतर्गत आयातों को शासित करने वाली संबंधित लाइसेंस शर्तों के तहत जारी किया गया है। लाइसेंस शर्तों और संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं को देखें और आयात/विदेशी भुगतान करते समय उचित कार्रवाई करें।

(2) उनसे निवेदन किया जाता है कि बैंक आफ इंडिया, टोकियो ब्रांच से दस्तावेज प्राप्त करने पर विदेशी संभरकों को येन भुगतान के बराबर रुपये जमा करने की व्यवस्था करें। संभरकों को चुकाई गई धन-राशि के बराबर रुपये की गणना सार्वजनिक सूचना सं. 8-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 17-1-76 और 113-आईटीसी (पीएन)/88-89 दिनांक 6-4-88 या अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना को समय-समय पर जारी की जाए के अनुसार विदेशी संभरकों को भुगतान करने की शर्तों को यथा प्रचलित परिवर्तन की निश्चित दर पर की जाएंगे। प्रथम 30 दिनों के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक दर से और इससे अधिक अवधि के लिए 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज जाकि संभरकों को भुगतान की तारीख/बैंक आफ इंडिया की प्रतिपूर्ति की तारीख और जिस तारीख को समुल्लेख रुपया भारत सरकार के लेखों में जमा किया जात उन दो अवधियों के बीच की अवधि के लिए संगणित करके उसे भी सार्वजनिक सूचना सं. 31-आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 10-8-83 और सार्व-जनिक सूचना सं. 15-आईटीसी (पीएन)/83, दिनांक 26-8-83 के अनुसार भारत सरकार के लेखों में जमा कराया है। ब्याज दोनों दिनों के लिए वेद है अर्थात् यह तारीख जिसको विदेशी संभरकों को भुगतान किया जाता है और यह भी तारीख जिसकी भारत सरकार के लेखों में रुपया जमा कराया जाता है। (जब भी इस दर में परिवर्तन किया जाए उसे सूचित कर दिया जाएगा)। 20-7-87 की सार्वजनिक सूचना सं. 230-आईटीसी (पीएन)/8-5-88 की शर्तोंनुसार आयातक द्वारा निक्षेप किए जाने वाले रुपये की गणना निकटतम रुपये के गुणक में की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आयातक की सीमाशुल्क निकासी के लिए आयात दस्तावेजों का मूल सैंट तैयार किए जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जाती है।

(3) वे धनराशियां जो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली भारतीय स्टेट बैंक, तीस हजारी में जाना के बहिनी धीर कोड सं. 5130000009 दर्शाते हुए जमा करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में उनका ध्यान सार्वजनिक सूचना सं. 603-आईटीसी (पीएन)/76, दिनांक 12-10-1976 में दिए गए प्रावधानों की धीर दिलाया जाता है। वह लेखा शीर्षों जिसमें रुपया जमा कराना है के डिपोजिट्स एण्ड एक्वाइजि-8443-सिविल डिपोजिट्स, डिपोजिट्स नोट बेयरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स-डिपोजिट्स फार परचेजिज एटसेट्रा अररोड परचेजिज अण्डर ग्रांट ऐड काम दि गवर्नमेंट आफ जापान आफ फार अण्डर डिटेल्ड लैंड 719 मिलियन येन ग्रांट एण्ड फार परचेजिज आफ इक्विपमेंट्स/सिविलिज फार पुणे इंजीनियरिंग कानेज, पुणे होगा।

(4) जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी दिल्ली में सार्वजनिक सूचना सं. 132-आईटीसी (पीएन)/71, दिनांक 5-10-1971 के अनुसार नकद जमा किए गए उन मामलों में बालन, को मूल रूप में एक प्रति-लिपि उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए, जिसके साथ बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणियों का पूर्ण विवरण देते हुए एक प्रेषण पत्र होना चाहिए:—

सहयता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक,
वित्त मंत्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग),
इंडिया प्रायल भवन, 5वां तल (बी बिल्डिंग),
जनपथ, नई दिल्ली-110001

(5) जिन मामलों में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना दिनांक 24-10-68 में यथा उल्लिखित दर्शाने वाली धुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसको सूचनाएं उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए। सभी मामलों में जमा किए गए तुल्य रुपये चुकाये गए ब्याज की राशि धीर वह अवधि जिसके लिए ब्याज गिना गया है, का पूरा ध्यौरा इस विभाग को भेजना चाहिए।

(6) ब्रांच के बैंक प्रभार धीर विदेशी संभरकों, के बैंकों के प्रभार, यदि कोई हों, तो वे भारतीय बैंक धीर बैंक ऑफ इंडिया, टोकियो के बीच सीधे तय किए जाने चाहिए।

(7) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत होकर के रूप में बैंक के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न परिपत्र में विनिर्दिष्ट किया गया है। इस संबंध में 18-6-1977 के ए.डी. परिपत्र सं. 22 की धीर विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. भारतीय दूतावास, टोकियो।

4. अवर सचिव, जापान अनुभाग, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई, दिल्ली को आई.डी.सं-----के संदर्भ में।
दिनांक-----के संदर्भ में।

(लेखा अधिकारी)

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

Public Notice No. 281 ITC(PN)/90—93

New Delhi, the 13th March, 1992

Subject :—Licensing conditions for import of equipment for the Government College of Engineering, Pune under Japanese Grant Aid for 1991-92 of Yen 719 Million—regarding.

File No. IPC/23(89)/90—93.—The terms and conditions for import of equipment for the Government College of Engineering, Pune and services necessary for the transportation of the equipments to ports in India from Japan under

Japanese Grant Aid for 1991-92 of Yen 719 million are contained in the Appendix to this Public Notice and notified for information.

Sd/-

D. R. MEHTA, Chief Controller of
Imports and Exports

APPENDIX TO THE MINISTRY OF COMMERCE

Public Notice No. 281 ITC(PN)/90-93, dated 13-3-92

Licensing conditions for import of equipment for the Government College of Engineering, Pune and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under Japanese Grant Aid for 1991-92 of 719 Yen Million (Yen 719,00,000).

Section I General Conditions :

I (i) The Japanese Grant Aid for 1991-92 of Yen 719 million is intended to be used for financing payments to Japanese suppliers for import of equipment and services necessary for the transportation thereof to ports in India.

I (ii) The import licences should be issued for an aggregate amount not exceeding Yen 790 million (CIF) in favour of the importer, and should bear the superscription "Yen 719 million Japanese Grant Aid for 1991-92". The licence code for the first and second suffix will be "S/JN". But no import licence is required for items covered under O.G.L.

I (iii) No remittance of foreign exchange will be permitted against the import licence, except bank charges to the Bank of India, Tokyo which may be remitted through normal banking channels, payment towards Indian Agent's Commission, if any, should be made in Indian rupees to the agents in India. Such payments, however, will form part of the licence value and will, thereof, be charged to the licence.

I (iv) The equipment should be procured only from Japan under this Grant Aid.

I (v) The import licences will be issued on CIF basis with validity upto 8-12-92.

I (vi) The contract should provide for payment on cash basis, i.e., on presentation of shipping documents by the Japanese suppliers to the Bank of India, Tokyo. It should also provide for the period of delivery as follows :—

"delivery to be completed by 8-12-92"

I (vii) The contract value (FOB or C&F basis, only) should be expressed in Yen (fraction of Yen should be omitted) and should exclude Indian Agent's Commission, if any. In no circumstances the contract value should be expressed in any other currency. The FOB cost and freight amount should be shown separately but it should be clarified in the contract itself whether the freight will be payable on actual basis or whether the freight charges indicated therein would be the amount payable irrespective of the actual charges.

I (viii) The purchase contract should be entered into only with the Japanese nationals or Japanese juridical person controlled by Japanese nationals. A certificate (in duplicate) showing the eligibility of the supplier should be added to each contract.

Section II : The following provision should be specifically incorporated in the supply contract.

II (i) The contract is arranged in accordance with the Agreement dated the 9th December, 1991 between the Governments of India and Japan concerning the Grant-Aid of Yen 719 million for 1991-92 and will be subject to the approval of both the Governments.

II (ii) Payments to the suppliers shall be made through an "Authorisation to Pay" (A/P) which will be issued by the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance,

Department of Economic Affairs, Janpath Bhavan, Vth Floor, (B Wing), Janpath, New Delhi-110001 in favour of the Bank of India, Tokyo under the Japanese Grant Aid for 1991-92.

II (iii) The Japanese suppliers agree to furnish such information and documents as may be required by the Government of India on the one hand and the Government of Japan on the other.

II (iv) The Japanese supplier agree to make shipping arrangements in consultation with the Embassy of India, Tokyo and that for this purpose he would keep the Embassy of India, Tokyo informed of the delivery schedule of the goods involved and notify the Embassy of India, at least six weeks in advance of the shipping required so that suitable arrangements should be made. In exceptional cases, where the importer require it this period of notice may be reduced. The Japanese supplier should also agree to send a cable advice to the importer after each shipment giving the necessary details and a copy thereof should be sent to the Embassy of India, Tokyo.

Section III : Contract Approval by Governments of India and Japan

III (i) As soon as the orders are finalised, the importer should forward to the Under Secretary (Jap.), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block, New Delhi 6 copies of the contract duly signed by both parties or purchase orders by the Indian importer placed on the Japanese supplier supported by order of confirmation in writing by the Japanese supplier or their photo copies complete in all respects together with two copies of the "Request for issue of A/P" in the form at Annex. I. The above procedure will also apply to all contract amendments causing essential modifications to the contents of contracts or in its price.

III (ii) The Ministry of Finance (DEA) Japan Section will arrange to send two copies of the contract to the Government of Japan for their approval for financing under the Japanese Grant Aid for 1991-92 of Yen 719 million, and one set of the documents mentioned in (i) above will also be sent to the CAA&A and the Embassy of India in Tokyo simultaneously.

III (iii) On receipt of the contract approval from the Government of Japan, the Japan Section of the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, North Block will inform the Controller of Aid Accounts & Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Janpath Bhavan, Vth Floor, B-Wing, Janpath, New Delhi-110001 of the same who will issue an 'Authorisation to Pay' (A/P) to the Bank of India, Tokyo in the form of Annexure II for making payment to the Japanese supplier. Copies of the A/P will be endorsed to the Embassy of India, Tokyo, the importer, importer's Bank in India and Japan Section, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance.

III (iv) On receipt of the Authorisation to Pay (A/P) the Bank of India, Tokyo will intimate the fact of this receipt to the Japanese supplier under intimation to the Government of Japan Embassy of India, Tokyo, the importers' Bank in India and the CAA&A.

III (v) The Japanese supplier shall, after effecting shipment present through his bankers the documents specified in the A/P to the BOI, Tokyo. If the documents are found to be in order, the Bank of India, Tokyo will release the amount specified in the documents to the Japanese supplier through his bankers.

III (vi) Banking charges payable to the Bank of India, Tokyo for arranging the payment to the Japanese supplier shall be settled by the concerned importer's bank in India by remittances to the BOI, Tokyo through normal banking channel without affecting the Government of India's account.

Section IV. Responsibility for rupee deposit

IV(i) The original negotiable shipping documents will be invariably forwarded by the Bank of India, Tokyo, to the concerned importer's bank in India which would be a branch of the State Bank of India or any of the nationalised banks as mentioned in (O) in Annexure-I who should release these negotiable set of documents to the importer concerned only after ensuring that the rupee equivalent of the Yen Payments made to the Japanese supplier alongwith interest charges thereon calculated at the rate of 12 per cent per annum for the first thirty days and at 18 per cent for the period in excess thereof reckoned from the date of payment by the Bank of India, Tokyo to the Japanese supplier to the date of actual rupee deposit, is deposited into Government of India account in terms of the Public Notice No. 31-ITC(PN)/83 dated 10-8-83 and No. 35-ITC(PN)/83 dated 26-8-83. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the day on which rupee deposit is made into Government account vide Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31-3-1974 as modified under Public Notice No. NI.103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976. In terms of Public Notice No. 230-17C(PN)/85-88 dated 20-7-87, the rupee deposits to be made by the importers is to be rounded off to the nearest rupee. The exchange rate to be adopted for computing the rupee equivalent of the Yen payment will be the prevailing composite rate of exchange as laid down in CCI&E Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17-1-1976 and No. 113-ITC(PN)/88-91 dated 6-4-89 or as may be notified by Government from time to time through Public Notices of the CCI&E or through Exchange control circulars of the Reserve Bank of India. Any change in this regard as also in regard to the rate of interest will be notified as and when necessary. It will be the responsibility of the Indian bank concerned to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the Import documents are handed over to the importers. The importer should also ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers. It is the responsibility of the importer to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government account promptly even when they obtain delivery of the goods from the customs authorities without original shipping documents under exceptional circumstances. In case the importer fails to deposit the amounts due to Government before taking delivery of the goods, the issue of further "A/P" to him may be stopped. The Head of Account to which the above rupee deposits should be credited is "K-deposits and Advances 8443-Civil Deposits not bearing interest, deposits for purchases etc., abroad-purchase under Grant Aid from the Government of Japan" for 1991-92 Grant for purchase of equipment/service for Government College of Engineering, Pune.

IV (ii) The amount referred to above should be deposited in cash to the credit of the Government either in the Reserve Bank of India, New Delhi Indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or if this is not possible, should be remitted by means of a demand draft obtained from any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or any one of the Nationalised Bank's Drawer drawn on and made payable to the State Bank of India, Tis Hazari Branch, Delhi-6 (drawee and payee) for credit to Government account as contemplated in Public Notices No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976.

IV (iii) The concerned bank in India shall also furnish such additional deposit in the same manner stipulated above as may be requested by the Government of India on account of service charges within seven days after such a demand is made by the Government. While filling in the various columns in the Challan it should be ensured by the Importers/their bankers that the information prescribed in Public Notice No. 103-ITC(PN)/76 dated 12-10-1976 is invariably indicated in the column "full particulars of remittances and authority (if any)" of the challan. The following particulars should invariably be furnished in the Treasury Challans:—

- (a) Ministry of Finance 'A/P' (Authorisation to Pay) No. and Date.

- (b) Amounts of Yen Currency in respect of which deposits are to be made together with rate of conversion adopted.

- (c) Date of payment to the Japanese supplier.

- (d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

- (e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the Japanese supplier upto and inclusive of the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee deposit should be sent by registered post to the CAA&A indicating reference to the A/P issued by him and also enclosing copies of invoice and shipping documents.

Note : Importer's Bank in India should ensure that the rupee deposits are invariably made within 10 days of the receipt of the advice of payment and negotiable shipping documents from the Bank of India, Tokyo and that the CAA&A, Ministry of Finance (DEA), New Delhi is informed immediately thereafter.

IV (iv) The concerned bank in India should also endorse the amount of rupee deposits on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" Form to the Reserve Bank of India, Bombay.

Section V : Miscellaneous provisions

V (i) Reports on the utilisation of the Grant Aid.—The importers should make separate arrangements to ascertain the amounts and dates of payments made to the supplier. Late or delayed receipt of shipping documents etc. by the importers Banker will not be acceptable as a reason for waiver of partial or full amount of the interest due on the rupee deposits.

The importer should send a monthly report after the A/P has been issued regarding shipments and payments made there against and about the balance left, to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Janpath Bhavan, Vth Floor, (B Wing), Janpath, New Delhi-110001.

V (ii) The importer should apprise the supplier of any special provisions in the import of goods under this Grant Aid which may affect the suppliers in carrying out the transaction.

V (iii) Disputes.—It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for dispute, if any that may arise between the importer and the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before payment by the Bank of India, Tokyo must be clearly spelt out by the importer in Annexure-I under "Terms of Payment". Provision dealing with a settlement of disputes be included in the condition of contract.

V (iv) Future Instructions.—The importer shall promptly comply with any directions, instructions or orders issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the imports and for meeting all obligations under the Grant Aid for from Japan.

V (v) Breach or violation.—Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the imports and Exports (Control) Act.

V (vi) List of Annexures :

Annexure I : Request for issue of A/P.

Annexure II : Form of A/P

ANNEXURE-I

REQUEST FOR ISSUE OF THE AUTHORISATION
TO PAY

To,

The Controller of Aid Accounts and Audit,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
'B' Wing, Vth Floor,
Janpath Bhavan, Janpath,
New Delhi.

Subject.—Import of Equipment for Government College of Engineering Pune. Services necessary for the transportation of the equipments to ports in India from Japan under the Japanese Grant Aid of Yen 719 million for 1991-92.

Sir,

In connection with the import of equipment and services necessary for its transportation of the Equipment from Japan under the above mentioned Grant Aid, we furnish the following particulars to enable you to issue the A/P to the B.O.I., Tokyo in favour of the Japanese supplier concerned :—

- (a) Name and address of Indian importer.
- (b) Number, Date and value of the import license and date upto which it is valid.
- (c) Method of Procurement whether it is based on direct purchase or limited open tendering in which case it should be indicated whether the contract has been awarded on the basis of technically suitable offer with reasons, if any.
- (d) Brief description of the goods.
- (e) Origin of the goods.
- (f) Gross C&F value of contract (in Yen).
- (g) Amount of Indian agents commission (in Yen), if any, payable in Indian rupees.
- (h) Net C&F value (in Yen) for which the A/P is required.
- (i) Number and date of the contract with Japanese suppliers.
- (j) Name and address of the Japanese supplier.
- (k) Payments terms and portable dates on which payments under the contract will fall due.
- (l) Expected date of completion of deliveries.
- (m) Documents to be presented at the time of payment to Bank of India, Tokyo (indicating No. of sets of each and their disposal).
- (n) Shipment instructions (indicate if transshipment/part shipment permitted or not permitted).
- (o) Name and address of the Importer's bank in India.
- (p) Who will bear the banking charges of the B.O.I., Tokyo—importer or supplier, please specify.
- (q) Undertaking by the importer :—

"We hereby undertake to make full and correct deposit of the rupee equivalent etc., of the payment made to the foreign supplier in the manner and at the rate prescribed by Government. The deposits will be made promptly before taking delivery of each consignment of the goods (material imported). In case of payments for services of foreign nationals, the deposits will be made as soon as the relevant invoices of the foreign suppliers made are approved by us and the payments made to suppliers".

Yours faithfully,

ANNEXURE-II

Authorisation to pay No.

(Government of India

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the

To,

The Bank of India,
Tokyo Branch,
Tokyo (Japan).

Subject.—Import of equipment and services necessary for the transportation of the equipment to ports in India from Japan under Japanese Grant-Aid of Yen 719 million, for 1991-92 Issue of Authorisation to Pay.

Dear Sirs,

In accordance with the terms and conditions of the agreement dated 9th December, 1991 entered into with your Bank, you are hereby authorised to pay an amount not exceeding Yen _____ to M/s. _____ as per details given in the appendix.

2. Please advise the Supplier of the fact of receipt of this Authorisation to pay (A/P) and endorse a copy of this advice to the Government of Japan, Importers Bank, Embassy of India, Tokyo and this Ministry.

3. Payments to the suppliers in terms of the A/P may be made on the basis of shipping documents as indicated in the appendix.

4. On making payments to the foreign suppliers, you should send to _____ to _____ (Name and address of importer's Banker) the original shipping documents (negotiable as well as additional complete set of the documents and a copy of the debit advice for the payments made to the supplier including the down payment if any).

5. Banking charges including charges for handling documents and charges of overseas suppliers, Bankers if any, payable to you by the importers, will be settled directly by the importer's bank.

6. As and when any payment is made by you on the basis of shipping documents presented by the Japanese supplier, an advice in the prescribed form should be sent to this Ministry and the importers' bank.

7. No amendment to this A/P may be advised in the absence of a specific authority from this Ministry.

8. This A/P will remain valid upto _____.

9. Please quote the number given at the top of this authorisation to pay in all correspondence relating to the contract and also in the advices showing payment.

Yours faithfully,

Accounts Officer

Copy forwarded to :—

1. Importer _____ with reference to their letter

No. _____ dated _____ They are requested to arrange to deposit through their bankers, the rupee deposits etc. at the prescribed rate and manner before taking delivery of the negotiable documents from the bankers. In case due to exceptional circumstances delivery of goods is obtained directly from the Customs and Port authorities without furnishing the original shipping documents, the deposits should be made before taking the delivery. In the case of payments for services rendered by foreign nationals, the deposits should be made as soon as the relevant invoices are approved for payment. Failure to make the deposits promptly and correctly may entail action as mentioned in the licensing conditions.

2. Importers' Banker—

(i) This authorisation to pay is issued under the relevant licensing conditions governing the imports under Yen grants. The licensing conditions and connected public notice/order etc. may be referred to and appropriate action taken concerning the import/foreign payments.

(ii) They are requested to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen payment to the Japanese supplier on receipt of the document from the Bank of India, Tokyo Branch. The rupee equivalent of amount disbursed to the suppliers will have to be calculated by applying the composite rate of conversion as prevailing on the date of payment to Japanese suppliers in accordance with the Public Notice No. 8-ITC(PN)/76 dated 17th January, 1976 and 113-ITC PN/88-89 dated 6th April, 1989 or such other Public Notices as may be issued from time to time interest @ 12 % per annum for the first thirty days and at the rate of 18% per annum for the period excess thereof reckoned for the period between the date of payment to the supplier and the date on which the rupee equivalent are deposited into the Government account, is required to be deposited into the Government of India's account in terms of public notices No. 31-ITC(PN)/83 dated 10th August, 1983 and No. 35-ITC(PN)/83 dated 26th August, 1983. The interest is payable for both the days i.e. the day on which payment is made to the Japanese supplier and also the date on which rupee deposit is made into the Government account (any change in this rate will be notified if and when made). In terms of Public Notice No. 230-ITC(PN)/85-88 dated 20th July, 1987 the rupee deposits to be made by the importers is to be rounded off to the nearest rupee. It should be ensured that these deposits are made before the original set of import negotiable documents are handed over to the importer for Customs Clearance.

(iii) These amounts should be deposited either with RBI, New Delhi indicating Code No. 5130000009 on the right hand corner of the Challan or in the S.B.I., Tis Hazari, Delhi or remitted by means of Demand Draft obtained by them from any Branch of the SBI of its subsidiaries or any one of the Nationalised Banks (Drawer) drawn on and made payable to the SBI, Tis Hazari, Delhi-6 (Drawee and Payee). In this connection their attention is also invited to the provisions of the Public Notice : No. 105-ITC(PN)/76 dated

12th October, 1976. The head of account to be credited is K-Deposits & Advances-8443-Civil Deposits, Deposit not bearing interest Deposit for purchases etc. abroad-purchases under grant aid from Government of Japan for under detailed head "Yen 719 million grant aid for purchases of equipment/services for Pune Engineering College, Pune.

(iv) One copy of the challan in original, in cases where the rupee equivalents are credited in cash at the RBI, New Delhi or the SBI, Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971, should be sent by them to the address given below alongwith a forwarding letter giving full details of the advice notes received from the Bank of India, Tokyo Branch.

The Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Janpath Bhavan, Vth Floor, (B-Wing), Janpath, New Delhi-110001.

(v) In cases where the rupee equivalents are remitted by means of demand drafts as laid down in the Public Notice dated 24th October 1968 mentioned above, intimations thereof should be sent to the address given above. In all cases, full particulars of the rupee equivalents deposited alongwith the amount of interest paid and the period for which interest has been calculated should be furnished to this Department.

(vi) The banking charges, of the Bank of India, Tokyo Branch, including charges of the overseas suppliers bankers, if any, should be settled directly between the Indian Bank and the B.O.I., Tokyo.

(vii) The Bank's duties and responsibilities as authorised dealer in foreign exchange are prescribed in various A.D. circulars of the R.B.I. specific reference in this regard is invited to A.D. Circular No. 22 dated 18th June, 1977.

3. Embassy of India, Tokyo.

4. The Under Secretary (Japan Section), Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi with reference to I.D. No. dated

()

Accounts Officer